Sl. No.	District		No. of Schemes	Project Cost	Loan Amount	Dwelling units
5.	Kutch Distt.	Urban Areas	—	—	—	—
		Rural Areas	6	3.62	1.42	2925
6.	Rajkot Distt.	Urban Areas	41	69.39	28.84	9470
		Rural Areas	11	6.54	3.11	11852
7.	Amreli Distt.	Urban Areas	5	4.81	3.50	1006
		Rural Areas	9	2.35	1.08	5725
			207	191.67	98.37	1,02,744

Complaints in the CPWD Service Centre in Netaji Nagar

2500. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of complaints of Type-I Government quarters in Netagji Nagar, New Delhi, pending with the CPWD service centre;

(b) the nature of complaints and since when the same have been pending;

(c) the reasons for their pendency; and

(d) the action taken/being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Only one complaint (Civil) is pending.

(b) The complaint pertains to plastering work, which is pending since 12.8.96.

(c) and (d) The complaint is pending due to incessant rains and will be attended to when the weather improves.

गुजरात में पिछड़े एवं शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार की योजनाएं

2501. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पिछड़े और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं का अद्यतन वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गई;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रावधान की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ): (क) और (ख) गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के पिछड़े और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई विशिष्ट स्कीम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि, संघ सरकार ने सूखा-प्रवण, मरुस्थल और जनजाति क्षेत्रों के लोगों के लाभ के लिए 1993-94 से रोजगार आश्वासन स्कीम शुरू की है, जो गुजरात के 218 ब्लॉकों में से 150 ब्लॉकों को कवर करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी स्कीमें जैसे कि छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी), नेहरू रोजगार योजना (एन॰ आर वाई) प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी-गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई यू पी ई पी), शहरी मूलभूत सेवा कार्यक्रम (यू बी एस पी) और तीव्रीकृत शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में शहरी समस्याओं के सुधार के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) योजना आयोग में कोई भी स्कीम स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।